

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289]	दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 25, 2019/कार्तिक 3, 1941	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 262
No. 289]	DELHI, FRIDAY, OCTOBER 25, 2019/KARTIKA 3, 1941	[N.C.T.D. No. 262

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2019

सं. 73/2018-राज्य कर

फा. सं. 3(58)/वित्त(राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/511.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 3), जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 51 के साथ पठित धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना संख्या 50/2018-राज्य कर, दिनांक 5 सितम्बर, 2019, जिसे सं. फा. 3(56)/वित्त(राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/413 दिनांक 5 सितम्बर, 2019, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह भी कि इस अधिसूचना की कोई बात ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय को लागू नहीं होगी जो उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन विनिर्दिष्ट एक व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति के बीच होता है।”

2. यह अधिसूचना दिसम्बर 31, 2018 से लागू मानी जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप-सचिव-VI (वित्त)

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्यांक 50/2018-राज्य कर, दिनांक 05 सितम्बर, 2019, जिसे सं. फा. 03(56)/वित्त(राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/413 दिनांक 05 सितम्बर, 2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण भाग-IV में प्रकाशित किया गया था और अंतिम संशोधन, जिसे सं.फा. 03(60)/वित्त(राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/510 दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 61/2018-राज्य कर, दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 द्वारा किया गया।

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 24th October, 2019

No. 73/2018-State-Tax

F. No. 3(58)/Fin (Rev-I)/2019-20/DS-VI/511.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1, read with section 51 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), hereafter in this notification referred to as the said Act, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-I), No. 50/2018-State Tax, dated the 5th September, 2019 published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3(56)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/413 dated the 5th September, namely:-

In the said notification, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that nothing in this notification shall apply to the supply of goods or services or both which takes place between one person to another person specified under clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-section (1) of section 51 of the said Act.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 31st day of December, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)

Note: The principal notification No. 50/2018-State Tax, dated the 5th September, 2019 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No.F.3(56)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/413 dated the 5th September, 2019 and was last amended by notification No.61/2018-State Tax, dated the 24th October, 2019 published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No.F.3(60)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/510 dated the 24th October, 2019.

अधिसूचना

दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2019

दिल्ली माल और सेवाकर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2019

आदेश सं. 04/2019-राज्य कर

फा. सं. 3(75)/वित्त(राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/512.—जबकि, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (एतस्मिन् पश्चात् इस आदेश में “उक्त अधिनियम” के रूप में संदर्भित) की धारा 17 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इतने इनपुट टैक्स तक सीमित रहेगा, जो करधान आपूर्ति के कारण होता है; और

और जहाँ कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3) में प्रावधान है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के उद्देश्य के लिए मूल्य बही होगा जो कि नियमों के द्वारा निर्धारित किया जायेगा;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **लघु शीर्षक**— यह आदेश दिल्ली माल एवं सेवा कर (कठिनाइयों का चौथा निराकरण) आदेश, 2019 कहलाएगा।
2. कठिनाइयों के निवारण के लिए एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, जिनपर कर लगता हो, जिनमें कि जीरो रेटेड आपूर्तियाँ और छूट प्राप्त आपूर्तियाँ भी आती हैं, से संबंधित क्रेडिट राशि का निर्धारण उस कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर के या उसके हिस्से के निर्माण के क्षेत्रफल पर आधारित होगा जो कि कर योग्य है और छूट प्राप्त है।
3. यह आदेश 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप-सचिव-VI (वित्त)

NOTIFICATION

Delhi, the 24th October, 2019

THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX (REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER, 2019 Order No. 04/2019-State Tax

F. No. 3(75)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/512.—Whereas, sub-section (2) of section 17 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the “said Act”) provides that the input tax credit shall be restricted to so much of input tax as is attributable to the taxable supplies;

And whereas sub-section (3) of section 17 of said Act provides that the value for the purpose of sub-section (2) of section 17 of the said Act shall be such as prescribed by rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 172 of the said Act, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title**—This Order may be called the Delhi Goods and Services Tax (Fourth Removal of Difficulties) Order, 2019.
2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that in case of supply of services covered by clause (b) of para 5 of Schedule II of the said Act, the amount of credit attributable to the taxable supplies including zero rated supplies and exempt supplies shall be determined on the basis of the area of the construction of the complex, building, civil structure or a part thereof, which is taxable and the area which is exempt.
3. This order shall come into force with effect from the 1st day of April, 2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)

अधिसूचना

दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2019

दिल्ली माल और सेवाकर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2019

आदेश स.05/2019-राज्य कर

फा. सं. 3(76)/वित्त(राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/513.—दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03)(जिसे इसमें इसके पश्चात ‘डीजीएसटी अधिनियम’ कहा गया है) की धारा 29 की उप-धारा (2), खंड (क) से खंड (ड) में वर्णित परिस्थितियों में उचित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का उपबंध करती है जो इस प्रकार से है, जहां :—

- (क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसे उपबंधों का उल्लंघन किया है जो विहित किए जाएं; या

- (ख) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति ने, तीन क्रमवर्ती कर अवधियों के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की है; या
- (ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने लगातार छह मास की अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की है; या
- (घ) किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने धारा 25 की उप-धारा (3) के अधीन स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण कराया है, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह मास के भीतर कारबार प्रारम्भ नहीं किया है; या
- (ङ) रजिस्ट्रीकरण कपट के साधनों से, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाने के द्वारा प्राप्त किया गया है;

परंतु उचित अधिकारी किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना रजिस्ट्रीकरण को रद्द नहीं करेगा।

और, डीजीएसटी अधिनियम की धारा 169 की उप-धारा (1) नोटिस की तामील (सुनवाई का अवसर) के लिए उपबंध करती है; उक्त उप-धारा के खंड (ग) और (घ) निम्न प्रकार से हैं :-

(ग) रजिस्ट्रीकरण के समय या समय-समय पर संशोधित उसके ई-मेल पते पर संसूचना भेजने के द्वारा; या

(घ) सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के द्वारा; या

और, धारा 30 की उप-धारा (1) रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए उपबंध करती है।

और, डीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (1) किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति के द्वारा, उस तारीख से जिसको ऐसे व्यक्ति को उक्त विनिश्चय या आदेश संसूचित किया जाता है, तीन मास के भीतर अपील फ़ाइल करने का उपबंध करती है और डीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (4) अपील प्राधिकारी को सशक्त करती है कि, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि, अपीलकर्ता तीन मास की पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था तो, वह उसे एक मास की और अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

और, डीजीएसटी अधिनियम की धारा 169 की उप-धारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के अनुसार उचित अधिकारी द्वारा नोटिस तामील के द्वारा सीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के अधीन बड़ी संख्या में रजिस्ट्रीकरण रद्द हुए हैं और डीजीएसटी अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) में रद्दकरण आदेश के प्रतिसंहरण के लिए उपबंधित तीस दिन की अवधि, डीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (1) के अधीन अपील फ़ाइल करने की अवधि और डीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (4) में विलंब के लिए क्षमा की अवधि भी व्यपगत हो गई है; रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनके रजिस्ट्रीकरण डीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के अधीन रद्द हो चुके हैं, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए सभी अपेक्षाओं को पूरा करने के बावजूद अपने रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण कराने में असमर्थ हैं। जी एस टी के एक नया अधिनियम होने के चलते, ये करदाता पहले की व्यवस्था की तुलना में, जहां नोटिस की तामील हाथ से होती थी, ई-मेल द्वारा या पोर्टल पर उपलब्ध कराये गए नोटिस की तामील की रीति से परिचित नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप डीजीएसटी अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कतिपय कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं;

अतः अब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफ़ारिशों पर, कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम – इस आदेश का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (कठिनाइयों को दूर करना-पांचवां) आदेश, 2019 है।

उक्त अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह कि, वह व्यक्ति जिसे धारा 169 की उप-धारा (1) के खंड (ग) या खंड (घ) में यथा उपबंधित रीति से धारा 29 की उप-धारा (2) के अधीन नोटिस तामील हुई थी और जो उक्त नोटिस का उत्तर नहीं दे सका है, जिसका परिणाम उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का रद्दकरण है, और इसलिए वह तारीख 31.03.2019 तक पारित ऐसे आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन फाइल करने में असमर्थ है, उसे 22.07.2019 तक रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।”

2. यह आदेश अप्रैल 23, 2019 से लागू माना जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप-सचिव-VI (वित्त)

NOTIFICATION

Delhi, the 24th October, 2019

THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX (REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER, 2019

Order No. 05/2019-State Tax

F. No. 3(76)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/513—WHEREAS, sub-section (2) of section 29 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the ‘DGST Act’) provides for cancellation of registration by proper officer in situations described in clause (a) to clause (e) as under: —

- (a) a registered person has contravened such provisions of the Act or the rules made thereunder as may be prescribed; or
- (b) a person paying tax under section 10 has not furnished returns for three consecutive tax periods; or
- (c) any registered person, other than a person specified in clause (b), has not furnished returns for a continuous period of six months; or
- (d) any person who has taken voluntary registration under sub-section (3) of section 25 has not commenced business within six months from the date of registration; or
- (e) registration has been obtained by means of fraud, willful misstatement or suppression of facts:

Provided that the proper officer shall not cancel the registration without giving the person an opportunity of being heard.

AND WHEREAS, sub-section (1) of section 169 of the DGST Act provides for service of notice (opportunity of being heard); clause (c) and (d) of said sub-section are as under: -

.....

- (c) by sending a communication to his e-mail address provided at the time of registration or as amended from time to time; or
- (d) by making it available on the common portal; or

.....

AND WHEREAS, sub-section (1) of Section 30 provides for revocation of cancellation of the registration within thirty days from the date of service of the cancellation order.

AND WHEREAS, sub-section (1) of section 107 of the DGST Act provides for filing appeal by any person aggrieved by any decision or order passed by an adjudicating authority within three months from the date on which the said decision or order is communicated to such person and sub-section (4) of section 107 of the DGST Act empowers the Appellate Authority that it may, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of three months, allow it to be presented within a further period of one month.

AND WHEREAS, a large number of registrations have been cancelled under sub-section (2) of section 29 of the DGST Act by the proper officer by serving notices as per clause (c) and clause (d) of sub-section (1) of section 169 of the DGST Act and the period of thirty days provided for revocation of cancellation order in sub-section (1) of section 30 of the DGST Act, the period for filing appeal under section (1) of section 107 of the CGST Act and also the period of condoning the delay provided in sub-section (4) of Section 107 of the DGST Act has elapsed; the registered persons whose registration have been cancelled under sub-section (2) of section 29 of the DGST Act are unable to get their cancellation of registration revoked despite having fulfilled all the requirements for revocation of cancellation of registration. GST being a new Act, these taxpayers were not familiar with the manner of service of notice by e-mail or making available at portal in comparison to earlier regime where manual service of notice was provided, as a result whereof certain difficulties have arisen in giving effects to the provisions of sub-section (1) of section 30 of the DGST Act;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely: —

Short title.—This Order may be called the Delhi Goods and Services Tax (Fifth Removal of Difficulties) Order, 2019.-

In sub-section (1) of section 30 of the said Act, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that the registered person who was served notice under sub-section (2) of section 29 in the manner as provided in clause (c) or clause (d) of sub-section (1) of section 169 and who could not reply to the said notice, thereby resulting in cancellation of his registration certificate and is hence unable to file application for revocation of cancellation of registration under sub-section (1) of section 30 of the Act, against such order passed up to 31.03.2019, shall be allowed to file application for revocation of cancellation of the registration not later than 22.07.2019.”.

2. This order shall come into force with effect from the 23rd day of April, 2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)